

रजिस्टर्ड नं० ल०/३३ एस०एम० १४/९२.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, २ दिसम्बर, १९९२/११ अग्रहायण, १९१४

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-२, १९ अगस्त, १९९२

सं० एल० एल० आर० (राजभाषा) बी (१६)-९/९२.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनूपुरक उपबन्ध) अधिनियम, १९८१ (१९८१ का १२) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश स्टेट एंड टू इन्डस्ट्रीज ऐक्ट, 1968 (1971 का 2)" के, संलग्न अधिप्रमाणित, राजभाषा रूपान्तर को एतद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा; और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो यह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम, 1968

(1971 का 2)

(को यथा विद्यमान)

राज्य सहायता अनुदान द्वारा हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम, 1968 है ।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

परिभाषाएं ।

(1) “बोर्ड” से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित उद्योग बोर्ड अभिप्रेत है ;

(2) “उधार लेने वाला” से वह व्यक्ति, कंपनी या संगम अथवा व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, अभिप्रेत है जिस को या जिसे इस अधिनियम के अधीन राज्य सहायता दी गई हो ;

(3) “कम्पनी” से कम्पनी अधिनियम, 1956 में यथा परिभाषित कम्पनी अभिप्रेत है ;

(4) “निदेशक” से निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन, निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है ;

(5) “उद्योग” से या तो व्यक्ति द्वारा या कम्पनी, संगम अथवा व्यक्ति निकाय द्वारा, चाहे वह निगमित हो या नहीं, संचालित या अपने ऊपर भार लिया हुआ कोई औद्योगिक कारखाना या उद्यम अभिप्रेत है ;

(6) “कुटीर उद्योग” से कोई उद्योग अभिप्रेत है, जो उस स्थान पर चलाया जा रहा है जो कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रयोजनों के लिए कारखाना नहीं है ;

(7) “ग्रामीण उद्योग” से कोई उद्योग अभिप्रेत है, जो राज्य की ग्रामीण जनसंख्या के किसी वर्ग की, चाहे पूर्ण-कालिक या अंश कालिक, सामान्य उपजीविका है ;

(8) “मशीनरी” के अन्तर्गत, किसी औद्योगिक संक्रिया या प्रसंस्करण के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संयंत्र, यंत्र, औजार और अन्य उपकरण है ;

(9) “राजपत्र” से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;

- (10) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
 (11) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ; और
 (12) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ।

अध्याय-2

उद्योग बोर्ड की स्थापना और उससे सम्बन्धित मामले

उद्योग बोर्ड की स्थापना। 3. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र संभव, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, निम्नलिखित सदस्यों से गठित बोर्ड स्थापित करेगी जिसे "उद्योग बोर्ड" कहा जाएगा, अर्थात् :—

- (क) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष ;
- (ख) निदेशक ;
- (ग) प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम ;
- (घ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए तीन गैर-सरकारी सदस्य ;
- (ङ) हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा, सभा के सदस्यों में से ही, तीन सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार होगा :

परन्तु बोर्ड को इस के समक्ष किसी विशिष्ट प्रश्न पर परामर्श के लिए, प्रश्नगत विषय पर सलाह देने की विशेष रूप से अहित या उस क्षेत्र की, जहां प्रश्नगत उद्योग स्थित है स्थानीय दशाओं की विशेष जानकारी रखने वाले, तीन से अधिक व्यक्तियों को आमन्त्रित करने की शक्ति होगी । बोर्ड द्वारा इस प्रकार आमन्त्रित व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(2) निदेशक बोर्ड का पदेन सदस्य होगा ।

(3) गणपूर्ति बोर्ड के चार सदस्यों से होगी ।

सदस्यों के निर्वाचन के व्यतिक्रम में प्रक्रिया । 4. यदि ऐसी तारीख तक जो राज्य सरकार द्वारा नियत की जाए, धारा 3(1) के खण्ड (ङ) के उपबन्धों के अधीन इस द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले किसी सदस्य को हिमाचल प्रदेश विधान सभा, निर्वाचित नहीं करती है, तो, राज्य सरकार उस सभा के एक सदस्य को, बोर्ड का सदस्य नियुक्त करेगी, मानो कि वह उस खण्ड के अधीन सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया था ।

उपाध्यक्ष । 5. बोर्ड, इसके सदस्यों में से एक को, ऐसी कालावधि के लिए जो यह उचित समझे, समय-समय पर उपाध्यक्ष निर्वाचित कर सकेगा ।

निर्वाचन या नियुक्तियों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना । 6. बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नियुक्त तथा निर्वाचित सदस्यों के नामों को राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

7. (1) उपाध्यक्ष या कोई अन्य नियुक्त अथवा निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष को लिखित नोटिस देकर अथवा पद त्याग सकेगा।

(2) (क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, नियुक्त किया गया सदस्य पांच वर्ष तक पद धारण करेगा; और निर्वाचित सदस्य पांच वर्ष तक या ऐसे समय तक जब तक उसका उसे निर्वाचित करने वाले निकाय का सदस्य रहना समाप्त नहीं हो जाता, जो भी लघुतर हो, पदधारण करेगा।

(ख) पदावरोही सदस्य, यदि अन्यथा अहित हो, पुनर्निर्वाचित या पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) उप-धारा (2) में उल्लिखित अवधि के अवसान के होते हुए भी, नियुक्त या निर्वाचित सदस्य तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उक्त अवधि के अवसान द्वारा हुई रिक्ति भर नहीं दी जाती, परन्तु कोई रिक्ति छः मास से अधिक के लिए खाली रहने नहीं दी जाएगी।

8. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को हटा सकेगी, यदि वह—

सदस्यों का हटाया जाना।

(क) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; या

(ख) दिवालिया घोषित किया जाता है; या

(ग) ऐसे किसी अपराध का सिद्धदोष पाया जाता है, या दण्ड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे आदेश के अधीन रखा गया है, जो राज्य सरकार की राय में चरित्र दोष विवक्षित करता है, जो उसे बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या सदस्य के रूप में बने रहने के अयोग्य करता है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस उप-धारा के अधीन सदस्य को हटाए जाने को अधिसूचित करने से पूर्व, संबद्ध सदस्य को, उसे हटाए जाने के कारण संसूचित किए जाएंगे और उसे लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा; या

(घ) राज्य सरकार की राय में, बोर्ड की चार से अधिक क्रमवर्ती बैठकों में, पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित है।

(2) राज्य सरकार ऐसी कालावधि निश्चित कर सकेगी जिसके दौरान इस धारा की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन इस प्रकार हटाया गया कोई व्यक्ति, पुनर्नियुक्ति या पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा।

9. जब बोर्ड के किसी सदस्य का स्थान उसके हटाए जाने, त्यागपत्र या मृत्यु द्वारा रिक्त होता है, तो राज्य सरकार द्वारा नया सदस्य नियुक्त किया जाएगा:

आकस्मिक रिक्तियाँ।

परन्तु यदि हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निर्वाचित किसी सदस्य का स्थान रिक्त होता है, तो सभा उसके स्थान पर अन्य सदस्य निर्वाचित करेगी, और निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एक संक्रमणीय मत द्वारा होगा:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन इस प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति उसी समय पर सेवानिवृत्ति के अध्याधीन होगा मानो वह उसी दिन बोर्ड का सदस्य बन गया था जिसको

वह सदस्य जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, पिछली बार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया था :

परन्तु यह और कि बोर्ड या उसके अधिकारियों का कोई कार्य केवल इस कारण से अधिविधमन्व नहीं समझा जाएगा कि ऐसे कार्य के अनुपालन के समय बोर्ड के सदस्यों की संख्या धारा 3 द्वारा उपबन्धित संख्या से कम थी।

भत्ते और फीस।

10. बोर्ड के सदस्यों और समितियों के सदस्यों को जो बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाएं, बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा उनको निर्दिष्ट किसी कर्तव्य के अनुपालन के लिए, जब आवश्यक हो, विहित रकम का यात्रा भत्ता विहित शर्तों पर संचित किया जाएगा।

बैठकों का सभापति।

11. (1) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, बोर्ड की प्रत्येक बैठक का सभापतिव करेगा और मत बराबर होने के सभी मामलों में उसका द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(2) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, किसी बैठक में उपस्थित सदस्य एक सदस्य को सभापतिव करने के लिए निर्वाचित कर सकेंगे, जिसका मत बराबर होने के सभी मामलों में द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

हितबद्ध सदस्य मत नहीं देंगे।

12. बोर्ड का कोई भी सदस्य, बोर्ड के समक्ष विचार के लिए आने वाले किसी प्रश्न पर (राज्य में सभी व्यक्तियों और सम्पत्तियों को इसके सामान्य उपयोजन से अन्यथा) जिसमें उसका धनीय हित हो मत नहीं देगा।

स्पष्टीकरण:—किसी ऐसे प्रश्न के उठने की दशा में कि क्या सदस्य का धनीय हित है या नहीं, अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति।

13. (1) बोर्ड, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों से संगत सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, विनियम बना सकेगा।

(2) विशेषतया और पूर्वगामी शक्ति की व्याप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों को विनियमित या अवधारित करने के लिए विनियम बना सकेगा, अर्थात् :—

- (i) इसकी बैठकों का समय और स्थान ;
- (ii) वह रीति जिसमें बैठकों का नोटिस दिया जाएगा ;
- (iii) बैठकों में कार्यवाहियों का संचालन ;
- (iv) बोर्ड के सदस्यों में कर्तव्यों का विभाजन ; और
- (v) बोर्ड के सदस्यों से पूर्णतः या ऐसे सदस्यों से भागतः और भागतः अन्य व्यक्तियों से गठित विशेष समितियों की नियुक्ति, कर्तव्य और प्रक्रिया।

बोर्ड का अधिक्रमण।

14. (1) यदि किसी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि बोर्ड इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस पर अधिरोपित कर्तव्यों का उचित रूप से अनुपालन नहीं कर रहा है, तो राज्य सरकार, बोर्ड द्वारा पेश किए गए किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात्, ऐसा करने के लिए कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित आदेश द्वारा, बोर्ड को विघटित कर सकती और निदेश दे सकती कि तदुपरि रिक्तियों, निर्वाचित सदस्यों के बार में निर्वाचन द्वारा और नियुक्त सदस्यों के बार में नियुक्ति द्वारा उपरोक्त उपदर्शित रीति में भरी जाएंगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से रिक्तियां भरने तक, बोर्ड की सभी शक्तियां और कर्तव्यों का ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति में प्रयोग और अनुपालन किया जाएगा, जैसी राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

15. बोर्ड का निम्नलिखित कर्तव्य होगा :—

बोर्ड का
कर्तव्य।

(क) राज्य सहायता के लिए आवेदनों पर जो इसकी राज्य सरकार द्वारा या इस द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सलाह के लिए इसको निर्दिष्ट किए जाएं, ऐसी जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जैसी यह आवश्यक समझे या जैसी इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित हो, राज्य सरकार को रिपोर्ट करना; और

(ख) किसी ऐसे विषय पर, जो इसको निर्दिष्ट किया जाए राज्य सरकार को सलाह देना :

परन्तु राज्य सरकार बोर्ड को निर्देश किए बिना, सिवाए उस ऋण के मामले में जिसकी रकम तीस हजार रुपये से अधिक न हो, राज्य सहायता मंजूर नहीं करेगी।

16. यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे, तो सचिव राज्य सरकार को कोई दस्तावेज अप्रेषित करेगा और बोर्ड के कार्य से संबंधित कोई रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करेगा।

राज्य
सरकार को
दिए जाने
वाले दस्ता-
वेज और
रिपोर्टें।

अध्याय-3

राज्य सहायता देने के बारे में साधारण उपबन्ध

17. जो राज्य सहायता दी जा सकेगी उसके रूप के अन्तर्गत निम्नलिखित हो सकेग, अर्थात् :—

राज्य सहा-
यता के रूप।

(क) ऋण का देना;

(ख) राज्य सरकार के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार में निहित भूमि, कच्ची सामग्री, पानी या कोई अन्य सांपत्तिक अधिकार का अनुकूल निबन्धनों पर देना, विक्रय करना या पट्टे पर देना;

(ग) बैंक के पास नकद उधार, ओवरड्राफ्ट या सावधि अग्रिम धन की प्रत्याभूति;

(घ) अवक्रीय पद्धति पर मशीनों का प्रदाय;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार नियत कालावधि के लिए संयुक्त स्टोक कम्पनी को सम्पूर्ण या भागतः पूंजी पर न्यूनतम आय की प्रत्याभूति;

(च) परिसीमित संयुक्त स्टोक कम्पनी द्वारा जारी स्टोक, शेयरज, बंधपत्र, या डिबेंचरज का हामीदारी;

(छ) शेयरों या डिबेंचरों का अर्जन, परन्तु ऐसे शेयरों या डिबेंचरों के लिए राज्य सरकार द्वारा संदत्त रकम उसी उद्योग में शेयरों और डिबेंचरों के लिए पहले से अन्य व्यक्ति द्वारा संदत्त रकम से अधिक नहीं होगी;

(ज) उद्योग को शुरू करने या सलाह देने के विशेषज्ञों या राज्य सरकार में सेवारत व्यक्तियों को, निशुल्क या अनुकूल निबन्धनों पर, सेवाएं देना ;

(झ) उपदान का संदाय —

(i) किसी बड़े पैमाने या मध्यम पैमाने के उद्योग की दशा में अनुसंधान के संचालन के लिए ;

(ii) किसी लघु उद्योग की दशा में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:—

(क) भूमि, मशीनरी और उपस्कर का क्रय ;

(ख) कारखाना इमारत, गोदामों, जल प्रदाय, भाण्डागारों का निर्माण ;

(ग) उद्योग में वास्तविक तौर पर उपयोग की जा रही मशीनरी में तकनीकी सुधार करना ;

(घ) सीमित कालावधि के लिए पर्याप्त प्रबन्धकीय और पर्यवेक्षी कामियों का नियोजन ;

(ङ) उद्योगों में नियोजित कर्मचारों का प्रशिक्षण ;

(च) अनुसंधान का संचालन ; और

(छ) नियम में विहित रीति में रियायती दर पर उस स्रोत से विद्युत ऊर्जा का प्रदाय करना जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है ।

उद्योग

जिनको

विभिन्न रूप

ही राज्य

सहायता दी

जा सकेगी ।

18. राज्य सहायता निम्नलिखित को दी जा सकेगी:—

(क) नया या उदीयमान उद्योग ; या

(ख) ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला नया उद्योग जहां ऐसे उद्योग अविकसित हैं ; या

(ग) कुटीर उद्योग या ग्राम उद्योग ; या

(घ) ऐसा उद्योग जिसके पुनः प्रवर्तित करने, या आधुनिक ढंगों से विकास की आवश्यकता हो ।

राज्य

सहायता को

आवेदन ।

19. राज्य सहायता के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में निदेशक को किए जाएंगे और उनमें ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट होगी, जैसी विहित की जाए ।

अध्याय-4

अवक्रम पद्धति पर मशीनरी के प्रदाय से अन्यथा दी जाने वाली राज्य सहायता विनियमित करने के उपबन्ध

ऋण देने की शक्ति ।

20. इस अध्याय के अधीन, राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन रहते हुए स्वीकृत ऋण वित्त विभाग से परामर्श के पश्चात्, दिए जाएंगे, परन्तु विहित रकम से अनधिक ऋणों के बारे में, राज्य सरकार ऐसे प्राधिकरण या अधिकारियों को, जैसे यह उचित समझे, अपनी गतियों का प्रत्यायोजन करते हुए नियम बना सकेगी ।

प्रतिसंदाय क लिए प्रतिभूति ।

21. (1) (क) ऋण के लिए आवेदन की स्वीकृति पर आवेदक विहित प्ररूप में, ऋण का उस प्रयोजन के लिए उपयोग करने का भार अपने ऊपर लेते हुए जिसके लिए, और उन शर्तों को पूरा करने जिन पर ऋण दिया गया था, स्वयं को और ऐसी सम्पत्ति जो कि

विलेख में विनिर्दिष्ट की गई है को यथा प्रतिभूति बनाते हुए, जिस के अन्तर्गत ऋण की सहायता से मशीनरी या निमित्त कोई इमारत भी है और ऐसी सम्पत्ति के अप्रयोज्य पाए जाने की दशा में, राज्य सरकार द्वारा ऋण देने या वसूली में उपगत व्यय और खर्च सहित, यदि कोई हो, ऋण के प्रति संदाय के लिए अपनी सारी सम्पत्ति को दायी बनाते हुए, एक विलेख निष्पादित करेगा।

(ख) उसमें विनिर्दिष्ट सम्पत्ति या ऋण की सहायता से खरीदी गई मशीनरी या निमित्त इमारत के सम्बन्ध में विलेख निष्पादन के बाद कोई अन्तरण, सुपुर्दगी या किश्या गया या सजित भार राज्य सरकार के विरुद्ध विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि यह ऋण मंजूर करने वाले प्राधिकारी की लिखित पूर्ण सम्पत्ति से नहीं किया या सजित किया गया हो।

(2) जब आवेदन फर्म या कम्पनी द्वारा किया गया है, तो विलेख उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित किया जाएगा और तदुपरि विलेख उक्त फर्म या कम्पनी पर आबद्धकर समझा जाएगा और उक्त फर्म या कम्पनी की सम्पत्ति ऋण के प्रतिसंदाय के लिए उसी प्रकार से दायी होगी माना कि ऋण किसी व्यक्ति को दिया गया हो।

22. ऋण उस पर सभी व्यय सहित, यदि कोई हो, या तो एक मुश्त राशि या किश्तों द्वारा, जैसा धारा 21 के अधीन उधार लेने वाले द्वारा निष्पादित विलेख में उपबन्धित किया जाए, प्रतिसंदाय होगा।

ऋण कैसे प्रतिसंदाय होगा।

23. (1) जब कोई ऋण या किश्त अथवा उस पर व्यय देय हो और देय तारीख को या उससे पहले संदत्त नहीं किया जाता है अथवा जब धारा 27 के अधीन ऋण तुरन्त प्रतिसंदाय घोषित किया गया हो, तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी, ऋण लेने वाले पर, विहित रीति में उस द्वारा देय रकमों का संदाय करने की या ऐसे समय के भीतर जो उस में नियत किया जाए कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए नोटिस की तामील करवा सकेगा।

संदाय का नोटिस।

(2) ऐसे नोटिस में यह सूचना होगी कि व्यक्तिक्रम की दशा में उक्त अधिकारी देय उधार की रकम और उसे तुष्ट करने के लिए विलेख में वर्णित यथादायी सम्पत्ति को दर्शित करते हुए विहित प्ररूप में घोषणा जारी करेगा।

24. (1) यदि, इस प्रकार नियत समय के भीतर, देय रकमों संदत्त नहीं की जाती हैं या धारा 23 के अधीन सशक्त अधिकारी के समाधानाप्रद रूप में कोई कारण दर्शित नहीं किया जाता है, तो उक्त अधिकारी उसी धारा की उप-धारा (2) में यथा वर्णित घोषणा जारी कर सकेगा और ऐसी घोषणा राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

घोषणा का प्रभाव।

(2) ऐसी घोषणा इसकी अन्तर्वस्तु की निश्चायक साक्ष्य होगी और उधार लेने वाले, उसके वारिसों, विधिक प्रतिनिधियों या समनुदेशित अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा, यदि वह संयुक्त हिन्दु परिवार से सम्बन्धित हो, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी, न ही उक्त व्यक्तियों या उनमें से किसी को लागू होने वाली स्वीय या रुद्धिजन्य विधि अथवा उसके अधीन पैदा होने वाला कोई अधिभार, सिद्धांत या नियम इस अधिनियम के अधीन निष्पादित बंधक या प्रकाशित घोषणा की विधिमान्यता या प्रभावशीलता पर अथवा उसके प्रवर्तन के लिए उसमें उपबन्धित प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) ऐसी घोषणा उक्त अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसको वह इस निमित्त साधारणतया या विशेषतया नियुक्त करे, आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय के समक्ष, जिसकी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर उधार के लिए दायी कोई सम्पत्ति स्थित है, उसी रीति में पेश की जा सकेगी जैसे वह डिक्री जिसका निष्पादन इच्छित हो।

घोषणा का
निष्पादन।

25. जब धारा 24 के अधीन सिविल न्यायालय द्वारा घोषणा प्राप्त कर ली गई हो, तो न्यायालय घोषणा में वर्णित सम्पत्ति को तुरन्त कुं करेगा और यह निर्देश देते हुए आदेश पारित करेगा कि, जब तक घोषणा में वर्णित रकम ऐसे समय के भीतर, जो दो महीने से अनाधिक न हो, जैसा न्यायालय युक्तियुक्त समझे, संदत्त नहीं की जाती है, तो यह घोषणा में वर्णित सम्पत्ति के विक्रय द्वारा वसूल की जा सकेगी मानों यह उक्त न्यायालय द्वारा इसकी सामान्य सिविल अधिकारिता के निष्पादन में धन के संदाय के लिए पारित डिक्री हो।

निरीक्षण
और
विवरणियां।

26. किसी भी मामले में जहां इस अध्याय के अधीन ऋण के लिए आवेदन किया गया हो, आवेदक और ऋण जो दिया गया है, के चालू रहने के दौरान किसी भी समय, ऋण लेने वाला निम्नलिखित के लिए आबद्ध होगा :—

- (क) उद्योग के परिसरों, इमारत, मशीनरी और उपलब्ध स्टॉक के निरीक्षण से सम्बन्धित, निदेशक के किसी सामान्य या विशेष आदेश का अनुपालन करने;
- (ख) उद्योग से सम्बन्धित सभी लेखों के निरीक्षण की अनुज्ञा देने;
- (ग) विनिर्मित या विक्रीत सभी उत्पादों का विवरण और परिमाण दोनों के विषयों में पूर्ण विवरणी देने;
- (घ) समय-समय पर ऐसे विशेष लेखे रखने और ऐसे कथन देने जैसे निदेशक अपेक्षा करे, और
- (ङ) उद्योग के लेखों को ऐसी संपरीक्षा के लिए, जैसी निदेशक विहित करे, प्रस्तुत करने।

ऋण के
उपयोजन में
व्यतिक्रम
के लिए
शास्ति।

27. यदि धारा 26 में उपबन्धित किसी निरीक्षण के पश्चात्, निदेशक का समाधान नहीं होता है कि उधार दिया गया धन उस/उन प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है जिसके लिए ऋण दिया गया था या व शर्तें, जिन पर ऋण दिया गया था, सम्यक् रूप से पूरी की जा रही हैं, तो वह धारा 21 के अधीन निष्पादित विलेख में किसी बात को होते हुए भी, घोषित कर सकेगा कि ऋण तुरन्त प्रतिसंवेद्य है और ऐसी घोषणा का ऋण लेने वाले को नोटिस देगा।

ऋण चालू
रहने के
दौरान प्रति-
भूति समा-
याजित करने
की शक्ति।

28. यदि, ऋण चालू रहने के दौरान किसी भी समय, प्रतिभूति का मूल्य परादेय ऋण के बकाया से कम पड़ जाता है, तो निदेशक या तो धाराओं 23, 24 और 25 में अधिकथित रीति में एस बकाया का उतना भाग जो कि विद्यमान प्रतिभूति के मूल्य के अन्तर्गत पर्याप्त रूप से नहीं आता है वसूल करने को अग्रसर हो सकेगा या ऐसी अतिरिक्त या सांप्रतिविक प्रतिभूति, जो वह पर्याप्त समझे, स्वीकार कर सकेगा।

ऋण वसूल
करने की
शक्ति।

29. यदि ऋण लेने वाला धारा 26 के खण्ड (क) के अधीन किसी आदेश का पालन करने में असफल रहता है या उद्योग से सापेक्ष लेखों का निरीक्षण करने की अनुज्ञा नहीं देता है या बाधा डालता है अथवा उक्त धारा के खण्डों (ग), (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट किन्हीं विशिष्टियों के बारे में व्यतिक्रम करता है, या यदि ऋण लेने वाला धारा 33 के उपबन्धों के उल्लंघन में लाभों को व्ययनित करता है, तो निदेशक, ऐसे समय के भीतर जो राज्य

सरकार इस निमित्त अनुज्ञात करे, ऋण लेने वाले के किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् धारा 23, 24 और 25 में अधिकथित रीति में ऋण वसूल करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

30. ऋण लेने वाला धारा 27, 28 और 29 के अधीन नोटिस की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा। अपील।

31. संयुक्त स्टॉक कम्पनी की पूंजी के संपूर्ण या भाग पर राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम प्रतिफल प्रत्याभूति की शर्तें निम्नलिखित होंगी :— न्यूनतम प्रतिफल पर सरकारी प्रतिभूति।

- (क) कि निरीक्षण, विवरणी और लेखों के बारे में उद्योग धारा 26 की शर्तों के अधीन होगा ;
- (ख) कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार उद्योग की प्राधिकृत पूंजी का नियत किए जाने वाला न्यूनतम प्रभाग अभिदत्त और नकद संदत्त किया गया है ;
- (ग) कि ऐसी कोई प्रत्याभूति किसी भी दशा में 5 वर्ष की कालावधि से परे विस्तारित नहीं होगी ;
- (घ) कि उस अवधि के दौरान जिसको प्रत्याभूति विस्तारित है, राज्य सरकार, ऐसे व्यक्तियों पर जिन्हें यह कम्पनी के उत्पन्न में प्रत्यक्षतः सम्बद्ध मानती है एक शर्त अधिरोपित कर सकेगी कि यदि वे अपने शेयरों को राज्य सरकार की सम्पत्ति के बिना अन्तर्गत करते हैं, तो वे कम्पनी को प्रत्याभूति की पूर्ति में संदत्त किन्हीं राशियों का राज्य सरकार को संयुक्तुतः और पृथक्तः प्रतिदाय करने को दायी होंगे ;
- (ङ) कि राज्य सरकार ऐसी प्रत्याभूति के कारण राज्य सरकार द्वारा संदत्त राशि का सम्पूर्ण या कोई भाग भूमि विकास ऋण अधिनियम, 1883 (1883 का 19) के अधीन दिए गए ऋणों के लिए करार की तारीख को प्रवृत्त दर पर ब्याज सहित ऐसी कालावधि के बाद किसी भी समय जैसी करार में अधिकथित की गई हो, वसूल करने की हकदार होगी, बशर्ते राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि कम्पनी समादत्त दर्शाई गई पूंजी पर, ऐसे दर से अधिक जैसे करार में निश्चित की जाए, ब्याज या लाभांश संदत्त कर रही है या संदत्त करने के योग्य है और ऐसी वसूली धारा 23, 24 और 25 में अधिकथित रीति में की जाएगी :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा किसी एक वर्ष में वसूलीय राशि कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में करार में निश्चित दर पर ब्याज और लाभांश के संदाय के लिए अपेक्षित राशि से अधिक कमाए शुद्ध लाभ के आधे के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी।

32. धारा 17 के खण्ड (अ) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर जैसी इस निमित्त विहित की जाएं, उद्योग को उपदान दिया जा सकेगा। उपदान।

33. कोई भी ऋण लेने वाला तब तक उद्योग की पूंजी की रकम पर ऐसी प्रतिशत दर के अतिरिक्त जो राज्य सरकार समय-समय पर नियत करें लाभांश संदत्त नहीं करेगा या लाभ वितरित अथवा प्राप्त नहीं करेगा जब तक वे शर्तें जिन पर राज्य सहायता दी गई है, पूरी नहीं की जाती हैं। उन शर्तों के पूरा न करने पर लाभों का व्ययन जब वे शर्तें जिन पर राज्य सहायता दी गई है।

सहायता प्राप्त उद्योग पर सरकारी नियन्त्रण।

34. इस अध्याय में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अपने निदेशकों की नियुक्ति द्वारा या अन्यथा, उस उद्योग के जिसको राज्य सहायता दी गई हो ऐसे संचालन का प्रयोग कर सकेगी, जो इसकी राय में इसकी हितों का संरक्षण करने के लिए पर्याप्त होंगे, बशर्ते ऐसा अधिकार सहायता देते समय करार द्वारा अभिव्यक्त रूप से आरक्षित किया गया हो।

देय धन की वसूली का ढंग।

35. धारा 23, 24 और 25 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को संदध रकम, जिसके अन्तर्गत उस पर प्रभार्य ब्याज और उपगत व्यय, यदि कोई हो, भी है राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

अध्याय--5

अवक्रय पद्धति पर मशीनरी का प्रदाय

भाड़ेदार द्वारा जमा की जाने वाली लागत की प्रति-शतता।

36. राज्य सरकार द्वारा अवक्रय पद्धति पर किसी मशीनरी का तब तक प्रदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका आवेदक निदेशक के पास, उसके खर्च का ऐसा प्रतिशत जैसा विहित किया जाए, निक्षिप्त नहीं करता है और ऐसे खर्च के असंदत प्रभाग के लिए अध्याय-4 के उपबन्धों के अधीन दिए गए ऋण की ही रीति में, प्रतिभूति नहीं देता है।

आवेदन अनुज्ञात किए जाने पर आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली विशिष्टियां।

37. जब आवेदन अनुज्ञात किया जाता है, तो निदेशक, इस अधिनियम के अधीन बनाए जाने वाले किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए और उन के अनुसार, निम्नलिखित विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा, अर्थात्:-

- (क) मशीनरी के भाड़े के लिए संदत की जाने वाली किराए की प्रत्येक किश्त की रकम और मशीनरी को भाड़े दार की सम्पत्ति बनने से पूर्व संदत की जाने वाली ऐसी किश्तों की संख्या ;
- (ख) शेष असंदत किश्तों पर, किराए की प्रत्येक किश्त के साथ संदत की जाने वाली ब्याज की रकम, यदि कोई हो ;
- (ग) तारीख जिस को और रीति जिसमें पूर्वोक्त संदाय किए जाएंगे ; और
- (घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी विहित की जाएं।

अवक्रय पद्धति पर मशीनरी के प्रदाय की शर्तें।

38. जब तक इसमें इसके पश्चात् उपबधित रीति में भाड़े पर दिया जाना समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे अर्थात्:-

- (क) भाड़ेदार, किराए की किश्तें और धारा 37 में निर्दिष्ट आदेश विनिर्दिष्ट ब्याज की रकम यथासमय और बिना मांग किए संदात करेगा ;
- (ख) भाड़ेदार, मशीनरी को अपने कब्जे में अच्छी और उपयोगी व्यवस्था और स्थिति में रखेगा और निदेशक की पूर्व लिखित सम्मति के बिना, उसका कोई परिवर्धन या उसमें परिवर्तन नहीं करेगा, न ही उसके प्रदाय के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट परिसरों से मशीनरी या उसका कोई भाग हटाएगा ;
- (ग) मशीनरी राज्य सरकार की एकमात्र और आत्यंतिक सम्पत्ति रहेगी और भाड़ेदार द्वारा उसका कोई अन्तरण या उसमें किसी अधिकार, हक या हित का समनुदेश अथवा

उस पर किसी बंधा विलगम या किसी अन्य प्रभार का सृजन राज्य सरकार के विरुद्ध शून्य होगा जब तक कि यह निदेशक की पूर्वलिखित सम्मति के साथ न किया गया हो;

(घ) मशीनरी इस अधिनियम के अधीन से अन्यथा तत्समय प्रवृत्त किसी अवधि के अधीन, किसी भी प्रक्रिया द्वारा करस्थम, कुर्की या विक्रय को दायी नहीं होगी;

(ङ) मशीनरी पर विहित आकार में एक धातु प्लेट होगी और कोई भी व्यक्ति जो ऐसी प्लेट को जानबूझकर हटाता है या विरूपित करता है, पांच सौ रुपये से अनाधिक जुर्माने का दायी होगा, जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो जाता, यह उपधारित किया जाएगा कि ऐसे धातु को प्लेट वाली मशीनरी इस अध्याय के अधीन भाड़े पर दी गई राज्य सरकार की सम्पत्ति है;

(च) भाड़ेदार सभी युक्तियुक्त समयों पर, निदेशक या निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को मशीनरी का निरीक्षण करना अनुज्ञात करेगा, और निदेशक या ऐसे अन्य व्यक्ति को निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करने की ऐसी सभी शक्तियां होंगी जो आवश्यक हों;

(छ) पूर्वगामी शर्तों के अतिरिक्त, भाड़ेदार उस से संगत ऐसी अन्य शर्तों द्वारा बाबद्ध होगा जैसी कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं या निदेशक द्वारा किसी विशेष मामले में अधिरोपित की जाएं।

39. यदि भाड़ेदार मशीनरी का किराया या ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि अथवा इस अध्याय के अधीन उससे देय कोई अन्य प्रभार संदत्त करने में व्यतिक्रम करता है या किन्हीं शर्तों का जो धारा 38 में अन्तर्विष्ट हैं या उसके अधीन अतिरोपित की जा सकेगी, अनुपालन करने में असफल रहता है, तो निदेशक उसको 16 दिन का नोटिस देने के पश्चात् भाड़े पर देना समाप्त कर सकेगा और तदुपरि वह या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उस परिसर में जिस में तत्समय मशीनरी रखी गई है प्रवेश कर सकगा चाहे ऐसा परिसर भाड़ेदार से सम्बन्धित हो अथवा नहीं, और उसका अभिग्रहण कर सकेगा और ले जा सकेगा।

भाड़ेदार द्वारा व्यतिक्रम का परिणाम।

40. (1) यदि धारा 39 के अधीन मशीनरी अभिगृहीत की जाती है और ले जाई जाती है तो, भाड़ेदार को ऐसे अभिग्रहण के एक महीने के भीतर या ऐसी दीर्घतर कालावधि में जैसी निदेशक द्वारा इस निमित्त अनुज्ञात की जाए, निदेशक को, ऐसी अन्य रकम सहित जो देय हो उसके खर्च के असंदत्त बकाया और ऐसे अभिग्रहण और ले जाने के आनुषंगिक खर्च और व्यय के संदाय द्वारा उसको खरीदने का, विकल्प प्राप्त होगा।

व्यतिक्रम के लिए अभिगृहीत मशीनरी खरीदने का भाड़ेदार का विकल्प।

(2) यदि, उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, भाड़ेदार खरीदने का विकल्प नहीं देता है, तो निदेशक, मशीनरी का निपटान करने को अग्रसर होगा।

41. यदि निदेशक धारा 39 के अधीन भाड़े पर देने का पर्यवसान करता है और भाड़ेदार धारा 40 के अधीन मशीनरी नहीं खरीदता है, तो भाड़ेदार, उस द्वारा धारा 36 के अधीन विक्षेप्त राशि के प्रतिदाय या भाड़े पर देने के दौरान उस द्वारा किए गए या से देय किसी संदाय के प्रतिदाय या माफी के लिए हकदार नहीं होगा, और ऐसी रकम के, यदि कोई हो, जैसी निदेशक धारा 40 की उप-धारा (2) के अधीन मशीनरी के निपटारे द्वारा कारित हुई किसी हानि के बारे में अवधारित कर, संदाय के लिए दायी होगा।

धारा 39 के अधीन भाड़े पर देने के पर्यवसान पर भाड़ेदार का दायित्व।

मशीनरी की 42. जब, धारा 36 के अधीन निक्षिप्त रकम के लिए ऋण दे दिया गया हो और लागत का भाड़ेदार ने धारा 37 के खण्ड (क) में उल्लिखित किराए की सभी किश्तों, और संदाय करने इस अध्याय के अधीन, उस द्वारा संदेय ब्याज की रकम, खर्च और अन्य प्रभार पर भाड़े पर पूर्ण संदत्त कर दिए हों, तो वह मशीनरी का स्वामी बन जाएगा और तदुपरि धारा देने का 38 के खण्ड (ड) में उल्लिखित धातु पट्टी उससे हटाएगा : पर्यवसान ।

परन्तु यदि, भाड़े पर देने के दौरान किसी भी समय, भाड़ेदार किराए की शेष किश्तें अग्रिम रूप से संदत्त करता है, तो उसके बारे में संदेय ब्याज माफ कर दिया जाएगा ।

मशीनरी 43. यदि, सम्यक् रूप से नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् भाड़ेदार स्वेच्छा से किसी पर से धातु पट्टी न हटाने के लिए शास्ति । मशीनरी पर से, जो धारा 42 के अधीन उसकी सम्पत्ति बन गई हो, धातु प्लेट नहीं हटाता है, तो वह पचास रुपये से अनधिक जुर्माने के लिए दायी होगा ।

इस अध्याय के अधीन देय राशि अध्याय 4 के अधीन ऋण के रूप में वसूलियां । 44. इस अध्याय के अधीन संदेय भी राशियां, अध्याय 4 के अधीन ऋण के रूप में ही वसूली होंगी ।

अध्याय-6

अनूपूरक

राज्य सरकार के 45. (1) राज्य सरकार का विनिश्चय कि इस अधिनियम में या इसके किन्हीं उपबन्धों के अधीन अधिकथित शर्तों का समाधान हो गया है, अन्तिम होगा और विनिश्चय तदधीन किए गए किसी आदेश को अपास्त करने या परिवर्तित करने के लिए किसी की अन्तिमता और सिविल सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा ।

और इण्ड (2) इस अधिनियम के अधीन शक्तियों से निहित किसी सरकारी अधिकारी न्यायालयों में या किसी अन्य प्राधिकारी के विरुद्ध, तदधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के वादी और लिए आशयित किसी बात के लिए, कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं कार्यवाहियों होगी । का वर्जन ।

नियम बनाने की 46. (1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इसके सभी या किन्हीं प्रयोजनों शक्ति । को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों को विनियमित या अवधारित करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) धारा 10 के अधीन याता अत्ता विनियमित करने ;

- (ख) धारा 19 के अधीन राज्य सहायता के लिए आवेदन करने की रीति ;
- (ग) धारा 20 के अधीन ऋण देने की शक्ति का प्रत्यायोजन करने ;
- (घ) धारा 21 के अधीन निष्पादित किए जाने वाले विलेख का प्ररूप ;
- (ङ) धारा 21 और 36 के अधीन राज्य सहायता के सम्यक उपयोजन और प्रति-संदाय या उस पर देय सभी ब्याजों सहित, यदि कोई हों, किराए के लिए ली जाने वाली प्रतिभूति की प्रकृति और रकम और ब्याज की दर जिस पर और वे शर्तें जिनके अधीन राज्य सहायता दी जा सकेंगी ;

परन्तु जहां प्रतिभूति पूर्णता या भागतः सम्बन्धित उद्योग के परिसरों, मशीनरी स्टॉक-स्टोरो या अन्य सम्पत्ति, वर्तमान या भविष्य की जंगम या स्थावर, से गठित है, वहां ऐसी सम्पूर्ण, सम्पत्ति वर्तमान और भविष्य की, जंगल और स्थावर, ऋण और उस पर देय सभी ब्याज, यदि कोई हों, की बसूली के लिए दायी बनाई जा सकेंगी ;

- (च) धारा 26 के अधीन परिसरों, इमारतों, मशीनरी और विद्यमान स्टॉक का निरीक्षण और लेखे रखने और संपरीक्षा करने का ढंग और किसी उद्योग के बारे में जिसे राज्य सहायता दी गई है की विवरणियां देना ;
- (छ) रीति जिसमें और स्थान जिस पर नोटिस या आदेश किसी उधार लेने वाले पर तामील किए जा सकेंगे ;
- (ज) धारा 24 के अधीन प्रयोग की जाने वाली घोषणा का प्ररूप,
- (झ) ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए कालावधि का नियम करना ;
- (ण) ऐसे मामले में धारा 33 के अधीन लाभों का उपयोजन जिसमें से शर्तें जिन पर राज्य सहायता दी गई है, पूरी नहीं की गई हों ;
- (ट) धारा 34 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों की नियुक्ति और कृत्य और उन उद्योगों के नियन्त्रण के अन्य ढंग विहित करना जिन को जिनको राज्य सहायता दी गई है ;
- (ठ) धारा 36 के अधीन जमा किए जाने वाले मशीनरी खर्च का प्रतिशत ;
- (ड) धारा 37 में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अतिरिक्त विशिष्टियां और वे शर्तें जिन पर अक्रय पद्धति पर मशीनरी का प्रदाय किया जा सकेगा ;
- (ढ) धारा 38 के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट धातु प्लेट का प्ररूप ;
- (ण) धारा 39 के अधीन नोटिस का प्ररूप ;
- (त) इस अधिनियम के अधीन संदेय किन्हीं राशियों की बसूली ; और
- (थ) इस अधिनियम के कामकाज से सम्बन्धित अन्य सभी विषय ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेंगी । यदि उस सत्र के या आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान से पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

निरसन और 47. (1) हिमाचल प्रदेश में यथा प्रवृत्त दि पंजाब स्टेट एंड टू इंडस्ट्रीज ऐक्ट, व्यावृत्तियां। 1935 (1935 का 5) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या कोई कारवाई, जिसके अन्तर्गत जारी किया गया कोई आदेश और अधिसूचनाएं या बनाए गए नियम भी हैं, जहां तक इस अधिनियम के उपबंधों से संगत हैं, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, की गई या जारी किए गए समझे जाएंगे।

(3) उप-धारा (1) के अधीन निरसित अधिनियम के अधीन दिए गए या दिए गए समझे जाने वाले सभी ऋण और उसके संबंध में निष्पादित किए गए सभी दस्तावेज इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए और बनाए गए समझे जाने वाले नियमों के उपबंधों के अधीन दिए गए और निष्पादित किए गए समझे जाएंगे, और उनकी वसुली तदनुसार की जाएगी।